

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 05.12.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :-

- उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्द ही स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन किया जाएगा।
- देहरादून में "साइबर भारत सेतु: ब्रिजिंग स्टेट्स, सिक्योरिंग भारत" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी-बीएलओ का कार्यभार कम करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को कहा।
- पंतनगर में आयोजित कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 संपन्न।

पहल

राज्य में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ शिक्षा को आधुनिक और रोजगारपरक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्द ही स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन किया जाएगा। एक रिपोर्ट-सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने की।

बैठक में परिषद के गठन, उसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि परिषद बनने के बाद राज्य में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ शिक्षा में एकरूपता आएगी और लाइसेंसिंग व पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

राष्ट्रीय अधिनियम लागू होने के बाद 10 श्रेणियों में 56 स्वास्थ्य सेवाओं को मान्यता मिलेगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। नए शामिल विषयों में पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डायलिसिस तकनीशियन, एनेस्थीसिया व ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, तथा आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन शामिल हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास

देहरादून में "साइबर भारत सेतु: ब्रिजिंग स्टेट्स, सिक्वोरिंग भारत" विषय पर कल दो दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सीईआरटी-उत्तराखंड और आईटीडीए द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया है।

सिविल सेवा संस्थान देहरादून में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आईटीडीए के निदेशक आलोक पांडेय ने कहा कि साइबर सुरक्षा लगातार जटिल होती जा रही है, इसलिए सभी विभागों और संस्थानों को पूरी तैयारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन संकटों से निपटने में बेहद उपयोगी होते हैं।

कार्यक्रम के पहले दिन विशेषज्ञों ने सीईआरटी-इन की भूमिका, उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। साइबर संकट प्रबंधन, हमलों के तौर-तरीकों और सुरक्षा उपायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई।

इस आयोजन में राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों के 150 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा प्रशासक शामिल हो रहे हैं।

मंजूरी

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड-यूजेवीएनएल बोर्ड की 131वीं बैठक में प्रदेश की कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 120 मेगावाट भ्योल रुपसियाबगड़, 102 मेगावाट मोरी त्यूणी और 114 मेगावाट सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों की पुनरीक्षित लागत भी मंजूर की गई।

यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निगम के विद्युत गृहों और अन्य घटकों को बीमित कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

साथ ही साढ़े तीन मेगावाट क्षमता की गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना के संशोधित टैरिफ के लिए नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कार्रवाई

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए कल विकास नगर, शिमला बाईपास और आसपास के इलाकों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। दून में छरबा स्थित होरोवाला रोड पर लगभग 4-5 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। मौके पर एमडीडीए की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून और आस-पास के क्षेत्रों का व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण भविष्य में नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाओं की दिक्कतें पैदा करते हैं, इसलिए अनधिकृत विकास किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि टीम लगातार मैदानी निरीक्षण कर रही है और जहां भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग मिल रही है, वहां कार्रवाई की जा रही है।

पिछले बुधवार को सेलाकुई के शेरपुर में भी लगभग बीस बीघा अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्वस्तीकरण किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण दृएसआईआर अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों-बीएलओ पर कार्यभार कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को आनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट-

कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 संपन्न

ऊधमसिंह नगर ज़िले के पंतनगर में आयोजित कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 संपन्न हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तीन दिन चले समागम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया।

श्रीमती आर्या ने कहा कि युवाओं को केवल शिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनमें अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का विकास करना भी आवश्यक है। ऐसे गुण युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं और वे देश के विकास में प्रभावी योगदान दे पाते हैं। उन्होंने कहा कि स्काउट और गाइड इन मूल्यों का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

रेखा आर्या ने युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने और अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विमोचन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नौसेना दिवस पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक विभाग पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने सेवारत और पूर्व नौ-सैनिकों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। उन्होंने एआई, स्वायत्त प्रणाली और उपग्रह दूरसंवेदन जैसी नई तकनीकों के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि इनका उपयोग समुद्री संचालन में बड़े बदलाव ला रहा है।

शीतकालीन यात्रा

रुद्रप्रयाग जिले के पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत और मंत्रोच्चार के साथ भव्य शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर गढ़वाल मंडल विकास निगम ऊखीमठ परिसर से ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखी और श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।

केदारनाथ क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी यात्रा का आरम्भ उसी उत्साह और भव्यता के साथ किया गया है। उन्होंने आशा जताई कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने आएंगे।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाएँ पहले ही दुरुस्त कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा से जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलता है और इससे स्थानीय लोगों की आजीविका भी मजबूत होती है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों...

पीसीएस मेन परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है – पीसीएस मेन्स परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दैनिक जागरण लिखता है– प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की खबर पर अमर उजाला लिखता है– शीतकालीन यात्रा का आगाज। राष्ट्रीय सहारा लिखता है – ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का आगाज।

प्रदेश में प्री-एसआईआर की गतिविधियों पर हिन्दुस्तान लिखता है– उत्तराखंड में प्री-एसआईआर पर वोटर को नहीं देने होंगे दस्तावेज। अमर उजाला लिखता है– एसआईआर: बीएलओ रोजाना 30 मतदाताओं से करेंगे मुलाकात।

बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के समाचार को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है – बिजली दरों में सोलह दशमलव तेईस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव मंजूर।